



Neutral Citation No. - 2026:AHC:59522

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 3481 सन् 2026

विपिन सिंह

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

...प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

:

कैलाश प्रकाश पांडे

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:

सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. इस रिट याचिका में दिनांक 10 फरवरी, 2026 के निलंबन आदेश को चुनौती दी गई है। चूंकि आक्षेपित आदेश को केवल विधिक आधार पर चुनौती दी गई है, इसलिए दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण ने शपथपत्रों के आदान-प्रदान के बिना इस याचिका के निस्तारण के लिए सहमति दी है।
3. निलंबन के आदेश को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यद्यपि किसी कर्मचारी को निलंबित करने की शक्ति प्रत्यर्थी के पास निहित है और इसका प्रयोग 1991 के नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के मद्देनजर किया जाना चाहिए, लेकिन दिनांक 14.02.2026 की पेपर बुक के पृष्ठ-37 पर प्रकाशित पत्र से यह स्पष्ट होता है कि निलंबन की शक्ति का प्रयोग प्रारंभिक जांच के दौरान किया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, उपरोक्त पत्र से यह स्पष्ट होता है कि विवादित आदेश शक्ति का दिखावटी प्रयोग है, जबकि नियमित विभागीय जांच की आवश्यकता के संबंध में कोई संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. यह निर्विवाद है कि 1991 नियमावली के तहत निलंबन की शक्ति के दायरे के संबंध में विधि, न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश द्वारा सच्चिदा नंद त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य [रिट ए संख्या 69308 सन् 2013] में दिए गए निर्णय के आलोक में तय हो चुका है। इसी तरह के प्रश्न पर विचार करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने सच्चिदानंद त्रिपाठी मामले में इस प्रकार कहा:-

"11. इस पहलू पर, राज वीर सिंह (उपरोक्त) मामले में पूर्ण पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों से मुझे बल मिलता है। प्रश्न (ख) का उत्तर देते हुए न्यायालय ने कहा कि नियमावली के अंतर्गत "जांच" शब्द में प्रारंभिक जांच शामिल नहीं हो सकती है और इसका अर्थ नियमित विभागीय जांच है, जैसा कि जय सिंह दीक्षित (उपरोक्त) मामले में वृहद पीठ ने कहा है और प्रश्न संख्या (ख) का उत्तर तदनुसार दिया गया था। हालांकि, प्रश्न संख्या (ख) और (ग) पर आगे विचार करते हुए, न्यायालय ने वृहद पीठ के निर्णय पर ध्यान दिया और कहा कि चाहे प्रारंभिक जांच की गई हो या नहीं, या यदि की गई हो, लेकिन पूरी नहीं हुई हो, तो यह अपने आप में निलंबन के आदेश को अमान्य नहीं करेगा, क्योंकि निलंबन के आदेश को वैध बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सक्षम प्राधिकारी ने सामग्री के वस्तुनिष्ठ विचार के आधार पर स्वयं को संतुष्ट कर लिया हो कि एक नियमित विभागीय जांच की परिकल्पना की गई है और यदि यह पहले से ही लंबित है, तो प्रारंभिक जांच का प्रश्न ही नहीं उठता। यह पैराग्राफ में कही गई बातों से स्पष्ट है। निर्णय के पैराग्राफ 43 और 46 को नीचे दिए गए अनुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

43. पूर्ण पीठ द्वारा दिया गया उत्तर संख्या 1 इस आशय का है कि 1991 के नियमावली का नियम 17(1)(क) प्रारंभिक जांच लंबित रहने के दौरान निलंबन आदेश पारित करने पर रोक नहीं लगाता है। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जय दीग दीक्षित मामले (उपरोक्त) में पांच न्यायाधीशों की वृहद पीठ ने सी.सी.ए. नियमावली के नियम 49-ए के संदर्भ में इस प्रश्न पर विचार किया था, जो एक समान नियम है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जवाहर लाल भार्गव (उपरोक्त) में तीन न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने यह मत व्यक्त किया है कि निलंबन आदेश पारित करने का अवसर तभी उत्पन्न होगा जब जांच करने का कोई ठोस निर्णय लिया जाए और इससे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पहले किसी भी समय निलंबन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जवाहर लाल भार्गव (उपरोक्त) में तीन न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ के उपरोक्त मत को पूर्ण पीठ ने अस्वीकृत कर दिया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जवाहर लाल भार्गव (उपरोक्त) में तीन न्यायाधीशों के निर्णय का तर्क यह था कि... प्रारंभिक जांच पूरी होने तक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलंबन के संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सकता। पांच न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने पैराग्राफ 37 में इस प्रश्न पर विचार करते हुए कि विभागीय जांच कब अपेक्षित मानी जा सकती है, यह स्पष्ट किया है कि विभागीय जांच तब अपेक्षित मानी जाती है जब वस्तुनिष्ठ रूप से विचार करने पर नियुक्ति प्राधिकारी मामले को विभागीय जांच के योग्य मानता है, चाहे कोई प्रारंभिक जांच, संक्षिप्त या विस्तृत, की गई हो या न की गई हो, या यदि की गई हो तो अधूरी हो। पूर्ण पीठ का उपरोक्त निर्णय स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करता है कि प्रारंभिक जांच की गई है या नहीं, या यदि की गई है तो अधूरी है, यह तथ्य प्रासंगिक नहीं है; प्रासंगिक है नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सामग्री का वस्तुनिष्ठ रूप से विचार करना। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जय सिंह दीक्षित मामले में पांच न्यायाधीशों की वृहद पीठ का निर्णय अभी भी मान्य है और उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, शाहरोज अनवर खान मामले (उपरोक्त) में पूर्ण पीठ द्वारा दिया गया उत्तर भी इसी के अनुरूप है। शाहरोज अनवर खान मामले (उपरोक्त) में पूर्ण पीठ के उत्तर संख्या 1 में कहा गया है कि प्रारंभिक जांच लंबित रहने के दौरान निलंबन आदेश पारित करने पर कोई रोक नहीं है। हालांकि, प्रारंभिक जांच लंबित रहने के दौरान पारित निलंबन आदेश वैध है या नहीं, यह एक अलग प्रश्न है जिसका उत्तर उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जय सिंह दीक्षित (उपरोक्त) मामले में बड़ी पीठ द्वारा निर्धारित कसौटी के अनुसार दिया जाना चाहिए, अर्थात् जब साक्ष्यों के वस्तुनिष्ठ विचार के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी मामले को विभागीय जांच के योग्य मानता है। इस प्रकार, शाहरोज अनवर खान के मामले में पूर्ण पीठ द्वारा दिया गया उत्तर संख्या 1, जिसमें यह कहा गया है कि प्रारंभिक जांच लंबित रहने के दौरान निलंबन आदेश पारित करने पर कोई रोक नहीं है, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जय सिंह दीक्षित मामले (उपरोक्त) में पांच न्यायाधीशों की वृहद पीठ के निर्णय के अनुरूप है, जैसा कि निर्णय के पैराग्राफ 37 में उल्लेख किया गया है। हालांकि, हम यह जोड़ना चाहते हैं कि जांच लंबित रहने के दौरान पारित निलंबन आदेश वैध है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

या नहीं, यह एक अलग प्रश्न है, जिस पर उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जय सिंह दीक्षित मामले में पांच न्यायाधीशों की वृहद पीठ के निर्णय के आलोक में विचार किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यदि निलंबन आदेश पैराग्राफ 99 में पांच न्यायाधीशों की वृहद पीठ द्वारा निर्धारित कसौटी को पूरा नहीं करता है, अर्थात् नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध सामग्री के आधार पर कोई वस्तुनिष्ठ विचार नहीं है कि औपचारिक विभागीय जांच अपेक्षित है, तो निलंबन को रद्द किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जय सिंह दीक्षित (उपरोक्त) मामले में माननीय न्यायमूर्ति सतीश चंद्र ने सहमति जताते हुए पैराग्राफ 72 में कहा है कि शक्ति के अस्तित्व को उसके दुरुपयोग से भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। प्रारंभिक जांच लंबित रहने के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी को निलंबन की शक्ति दी जा सकती है, लेकिन क्या इस शक्ति का वैध रूप से प्रयोग किया गया है, यह एक अलग प्रश्न है जिस पर उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जय सिंह दीक्षित मामले में पांच न्यायाधीशों की वृहद पीठ के फैसले के आलोक में अलग से विचार किया जाना चाहिए। पांच न्यायाधीशों की वृहद पीठ ने अपने फैसले के पैराग्राफ 72 में निम्नलिखित बातें कही हैं:-

"72. शक्ति का अस्तित्व उसके दुरुपयोग से भ्रमित नहीं होना चाहिए। दुरुपयोग की स्थिति में, शक्ति का वह विशेष प्रयोग गलत होगा और उसे रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि नियम की उचित व्याख्या के अनुसार शक्ति कब उत्पन्न होती है।

"46. कृपा शंकर प्रसाद मामले (उपरोक्त) में डिवीजन बेंच द्वारा लिया गया यह मत कि प्रारंभिक जांच का निर्देश देते समय निलंबन का आदेश नहीं दिया जा सकता था, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जय सिंह दीक्षित मामले (उपरोक्त) में पांच न्यायाधीशों की वृहद बेंच के मत के अनुरूप नहीं है, और इसलिए शाहरोज अनवर खान मामले (उपरोक्त) में पूर्ण बेंच द्वारा दिए गए उत्तर संख्या 2 पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रारंभिक/तथ्य-खोज जांच के लंबित रहने के दौरान पारित निलंबन आदेश को चुनौती पर विचार करते समय, निलंबन आदेश की सत्यता या असत्यता की जांच के लिए लागू किया जाने वाला मानदंड यह है कि क्या सामग्रियों के वस्तुनिष्ठ विचार के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी इस मामले को विभागीय जांच का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पात्र मानता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जय सिंह दीक्षित मामले में पांच न्यायाधीशों की बड़ी बेंच द्वारा निर्धारित किया गया है। चूंकि इन मुद्दों को पांच न्यायाधीशों की वृहद बेंच द्वारा पहले ही कवर किया जा चुका है, इसलिए प्रश्न संख्या (ख) को बड़ी बेंच के संदर्भ की आवश्यकता नहीं है।

12. न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि निलंबन का आदेश विभागीय जांच के विचार में नहीं बल्कि प्रारंभिक जांच के लंबित रहने या विचार में पारित किया गया है, तो राज्य सरकार को आवश्यक सामग्री अभिलेख पर रखकर यह सिद्ध करना होगा कि प्रारंभिक जांच के बावजूद, संबंधित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट था कि मामले के तथ्यों के आधार पर निलंबन उचित था। राजवीर सिंह (उपरोक्त) मामले में दिए गए फैसले का पैरा 47 इस प्रकार है:

"47. क्या प्रारंभिक जांच का निर्देश देते समय निलंबन की शक्ति का प्रयोग प्रत्येक मामले के अभिलेख में मौजूद सामग्री के वस्तुनिष्ठ विचार के आधार पर किया जाना चाहिए, और इसलिए यह राज्य सरकार का दायित्व है कि यदि जांच के मददेनजर निलंबन के आदेश को चुनौती दी जाती है, तो वह अभिलेख में मौजूद ऐसी सामग्री के आधार पर यह सिद्ध करे कि प्रारंभिक जांच के बावजूद प्राधिकारी संतुष्ट था कि मामले के तथ्यों के आधार पर निलंबन उचित था।"

13. न्यायालय, किसी अन्य सामग्री के अभाव में, यह निष्कर्ष निकालने में उचित होगा कि निलंबन का आदेश, जिसमें स्वयं में प्रारंभिक जांच का निर्देश देने और प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उल्लेख है, केवल प्रारंभिक जांच के मददेनजर या उसके लंबित रहने के दौरान निलंबन का आदेश है, और सक्षम प्राधिकारी के पास नियमित विभागीय जांच के बारे में वस्तुनिष्ठ विचार दर्शाने वाली कोई सामग्री नहीं है। आदेश में, जहां प्रारंभिक जांच के संचालन के साथ-साथ जांच की परिकल्पना का उल्लेख किया गया है, जब तक कि प्रत्यर्थी-सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित दलीलों और सामग्री के माध्यम से वस्तुनिष्ठ विचार प्रदर्शित नहीं किया जाता है, न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई वस्तुनिष्ठ विचार नहीं किया गया है और निलंबन का आदेश उचित विचार-विमर्श के बिना, यांत्रिक रूप से पारित किया गया है। एक ओर, यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि जैसे विधि की आवश्यकता पूरी हो गई हो, वहीं दूसरी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ओर, सक्षम प्राधिकारी को राय बनाने के लिए आवश्यक सामग्री अभिलेख में उपलब्ध न होने के कारण, ऐसी सामग्री एकत्र करने के लिए प्रारंभिक जांच का आदेश पारित किया गया है। वास्तव में, ऐसी जांच एक तथ्य-खोज जांच है जो बाद में सक्षम प्राधिकारी को मामले में उचित निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक सामग्री उपलब्ध कराएगी। इस प्रकार का आदेश, वास्तव में, शक्ति का दिखावटी प्रयोग है और ऐसे मामले में इसे बरकरार रखना मुश्किल है जहां राज्य अपने आदेश को उचित ठहराने में बुरी तरह विफल रहा है, जैसा कि राजवीर सिंह (उपरोक्त) के फैसले के पैरा 47 में उल्लेख किया गया है।"

5. उपर्युक्त विधिक स्थिति और प्रारंभिक जांच लंबित होने के बावजूद अपेक्षित संतुष्टि प्राप्त होने के प्रमाण के अभाव में, निलंबन का आक्षेपित आदेश अस्थिर घोषित किया जाता है।

6. तदनुसार और सच्चिदानंद त्रिपाठी (उपरोक्त) मामले में दिए गए कारणों का अनुसरण करते हुए, यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है। दिनांक 10 फरवरी, 2026 का आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है। हालांकि, यह आदेश प्रत्यर्थीगण को विधि और 1991 के नियमावली में दिए गए प्रावधानों के अनुसार नई कार्यवाही शुरू करने से नहीं रोकता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

23 मार्च, 2026

स्वाति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।